इक्कीसवीं सदी में किन्नर समाज की संवैधानिक स्थिति

रोहित कुमार (शोधार्थी)

तुलनात्मक भाषा एवं संस्कृति अध्ययन शाला

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर मध्य प्रदेश

शुभ अवसरों पर बधाई के मंगल गान गाने वाले मंगलामुखी किन्नरों को सुप्रीम कोर्ट ने पहचान के साथ कानूनी दर्जा देने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ किन्नरों को लिंग की तीसरी श्रेणी में शामिल करने का, बल्कि उन्हें शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और नौकरियों में आरक्षण देने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने किन्नरों को बराबरी का हक देते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे किन्नरों की सामाजिक और लिंगानुगत समस्याओं का निवारण करें। इतना ही नहीं उन्हें चिकित्सा व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएं।

न्यायमूर्ति के एस राधाकृष्णन व न्यायमूर्ति एके सीकर की पीठ ने किन्नरों को पहचान के साथ कानूनी दर्जा मांगने वाली नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी , किन्नरों के कल्याण के लिए काम करने वाली संस्था पूज्य माता नसीब कौर जी वूमेन वेलफेयर सोसाइटी तथा किन्नर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की याचिकाएं स्वीकार करते हुए यह आदेश सुनाया है। कोर्ट ने किन्नरों को बराबरी का कानूनी हक देते हुए केंद्र व राज्य सरकारों को नौ दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पीठ ने कहा कि संविधान में सभी को बराबरी का दर्जा दिया गया है और लिंग के आधार पर भेदभाव की मनाही की गई है। यह मौलिक अधिकार का हनन है। संविधान में बराबरी का हक देने वाले **अनुच्छेद 14, 15, 16 और 21** का लिंग से कोई संबंध नहीं हैं। इसलिए ये सिर्फ स्त्री, पुरुष तक सीमित नहीं है। इनमें किन्नर भी शामिल हैं।

कोर्ट ने कहा कि किसी का लिंग उसकी आंतरिक भावना से तय होता है कि वह पुरुष महसूस करता है या स्त्री या फिर तीसरे लिंग में आता है। किन्नर को न तो स्त्री माना जा सकता है और न ही पुरुष। वे तीसरे लिंग में आते हैं।

इन्हें बच्चा गोद लेने का भी अधिकार है

किन्नर एक विशेष सामाजिक धार्मिक और सांस्कृतिक समूह है इसलिए इन्हें स्त्री, पुरुष से अलग तीसरा लिंग माना जाना चाहिए। कोर्ट ने देश विदेश में किन्नरों के कानूनी दर्जे पर भी चर्चा की है। कोर्ट ने कहा है कि पंजाब में सभी किन्नरों को पुरुष माना जाता है जो कि कानूनन ठीक नहीं है। केरल, त्रिपुरा और बिहार में किन्नरों को तीसरे लिंग में शामिल किया गया है। कुछ राज्यों में उन्हें तीसरी श्रेणी माना गया है। तमिलनाडु ने किन्नरों के कल्याण के लिए काफी कुछ किया है। कोर्ट ने कहा कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल और पाकिस्तान ने भी उन्हें पहचान और कानूनी हक दिए हैं।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में स्व पहचान का अधिकार शामिल है। कोर्ट ने किन्नरों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा बताते हुए केंद्र व राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि शैक्षणिक संस्थानों व नौकरियों में पिछड़ों को दिया जाने वाला आरक्षण किन्नरों को भी दें। कोर्ट ने कहा है कि किन्नरों की दशा पर विचार कर रही सरकार की कमेटी तीन महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दे। सरकार रिपोर्ट पर विचार कर इस फैसले को ध्यान में रखते हुए छह महीने के भीतर इसे लागू करे।

1- किन्नरों को तीसरे लिंग के तौर पर शामिल कर संविधान और कानून में मिले सभी अधिकार और संरक्षण दिए जाएं

2- किन्नरों को अपने लिंग की पहचान तय करने का हक है। केंद्र व सभी राज्य सरकारें उन्हें कानूनी पहचान दें।

3- किन्नरों को सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ा मानते हुए शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और नौकरियों में आरक्षण दिया जाए।

4- किन्नरों की चिकित्सा समस्याओं के लिए अलग से एचआइवी सीरो सर्विलांस केंद्र स्थापित करें।

5- किन्नरों की सामाजिक समस्याओं जैसे भय, अपमान, शर्म व सामाजिक कलंक आदि के निवारण के गंभीर प्रयास करें।

6- किन्नरों को अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए और अलग से पब्लिक टायलेट व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएं।

7- सरकारें किन्नरों की बेहतरी के लिए सामाजिक कल्याण योजनाएं बनाएं।

8- सरकार किन्नरों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करने के प्रयास करे ताकि किन्नर अपने को अछूत या अलग-थलग न महसूस करें।

9- किन्नरों को उनकी पुरानी सांस्कृतिक और सामाजिक प्रतिष्ठा की पहचान दिलाने के लिए कदम उठाएं।

कोर्ट ने कहा कि किसी का लिंग उसकी आंतरिक भावना से तय होता है कि वह पुरुष महसूस करता है या स्त्री या फिर तीसरे लिंग में आता है। किन्नर को न तो स्त्री माना जा सकता है और न ही पुरुष। वे तीसरे लिंग में आते हैं।

सन 2018 में एक किन्नर रेशमा प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी । इसमें केंद्र से आधार कार्ड की तरह पैन कार्ड पर तृतीय लिंग के विकल्प देने के लिए की गई थी। ताकि किन्नर पैन और आधार को लिंक अथवा जुड़वा सकें ।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने बताया कि याचिका को लंबित रहने के दौरान हमने सरकार से जवाब मांगा था । अब सरकार ने बताया है कि उन्होंने याचिका में उठाई गई सभी मांगों को स्वीकार कर लिया है। अब किन्नर लोग (**प्रोटेक्सन ऑफ राइट्स) एक्ट 2019 की धारा 6 और 7** के तहत जारी किया जाना वाला प्रमाण पत्र मंजूर होगा। यह जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी किया जाता है।

लिंग का संबंध पुरुष या महिला से है। यह जीवन का एक मूलभूत पहलू है जिसके द्वारा मनुष्य की पहचान पुरुष, महिला या ट्रांसजेंडर या ट्रांससेक्सुअल व्यक्ति के रूप में की जाती है। किसी भी मनुष्य का लिंग जैविक और शारीरिक पहलू होता है। कोई व्यक्ति पुरुष है या महिला, यह शारीरिक संरचना के आधार पर निर्भर करता है। कुछ लोगों में दोनों तरह की प्रवृत्तियाँ होती हैं, यानी पुरुष और महिला। कई बार जननांग स्वायत्तता कई समस्याएँ पैदा करती है, कुछ लोगों का व्यवहार समाज की धारणा के अनुसार उन्हें दिए गए लिंग के अनुसार नहीं हो सकता है।

दुनिया भर के देशों में, भारत सहित, ऐसे व्यक्तियों को लिंग के निर्धारण के सवाल का सामना करना पड़ा जो मानते हैं कि वे विपरीत लिंग के हैं। कुछ लोगों ने अपनी प्रवृत्ति के अनुसार पुरुष या महिला की विशेषताओं को प्राप्त करने के लिए शरीर को बदलने के लिए शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं से गुज़रा था, लेकिन इसके परिणामस्वरूप कानूनी और सामाजिक जटिलताएँ पैदा हुईं क्योंकि जन्म के समय उनके लिंग का आधिकारिक रिकॉर्ड माना जाने वाला लिंग पहचान से भिन्न पाया गया।

लिंग पहचान प्रत्येक व्यक्ति के लिंग के बारे में गहराई से महसूस किए गए आंतरिक और व्यक्तिगत अनुभव को संदर्भित करती है, जो जरूरी नहीं कि निर्धारित लिंग के अनुरूप हो। इसलिए, लिंग पहचान एक व्यक्ति की पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर या अन्य पहचानी गई श्रेणी के रूप में स्वयं की पहचान को संदर्भित करती है।

भारत कई अंतरराष्ट्रीय संधियों का हस्ताक्षरकर्ता है, जो लिंग पहचान के आधार पर समानता और गैर-भेदभाव की गारंटी देता है। यूएनडीपी इंडिया रिपोर्ट पहचान, संस्कृतियों या अनुभवों को समझने के लिए सबसे अच्छा दस्तावेज है।

“हिजड़ा: हिजड़ा जैविक पुरुष हैं जो समय के साथ अपनी ‘मर्दाना’ पहचान को अस्वीकार कर देते हैं और या तो महिला, या “गैर-पुरुष”, या “पुरुष और महिला के बीच में”, या “न तो पुरुष और न ही महिला” के रूप में पहचान करते हैं। हिजड़ों को ट्रांसजेंडर/ट्रांससेक्सुअल (पुरुष से महिला) व्यक्तियों के पश्चिमी समकक्ष के रूप में माना जा सकता है, लेकिन हिजड़ों की एक लंबी परंपरा/संस्कृति है और उनके मजबूत सामाजिक संबंध हैं

जिन्हें "रीत" (हिजड़ा समुदाय का सदस्य बनना) नामक एक अनुष्ठान के माध्यम से औपचारिक रूप दिया जाता है। हिजड़ों को संदर्भित शब्दों के उपयोग में क्षेत्रीय भिन्नताएँ हैं। उदाहरण के लिए, किन्नर (दिल्ली) और अरावनी (तमिलनाडु)। हिजड़े अपने पारंपरिक काम के माध्यम से कमा सकते हैं: 'बधाई' (अपने हाथों से ताली बजाना और भीख माँगना), नवजात शिशुओं को आशीर्वाद देना, या समारोहों में नृत्य करना।

कुछ हिजड़े अन्य नौकरी के अवसरों की कमी के कारण सेक्स वर्क में संलग्न हैं, जबकि कुछ स्वरोजगार कर सकते हैं या गैर-सरकारी संगठनों के लिए काम कर सकते हैं।

हिजड़ा: हिजड़ा एक नपुंसक पुरुष को संदर्भित करता है और एक ऐसे व्यक्ति को इंटरसेक्स किया जाता है जिसके जननांग जन्म के समय अस्पष्ट रूप से पुरुष जैसे होते हैं, लेकिन यह पता चलने पर कि बच्चा पहले पुरुष लिंग का है, उसे फिर से इंटेसेक्स्ड - हिजड़ा के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। "अरावनी और 'थिरुनांगी' - तमिलनाडु में हिजड़े "अरावनी" के रूप में पहचाने जाते हैं।

तमिलनाडु अरावनीगल कल्याण बोर्ड, समाज कल्याण विभाग के तहत राज्य सरकार की एक पहल है, जो अरावनी को जैविक पुरुषों के रूप में परिभाषित करती है जो खुद को एक पुरुष के शरीर में फंसी हुई महिला के रूप में पहचानते हैं। कुछ अरावनी कार्यकर्ता चाहते हैं कि जनता और मीडिया अरावनी को संदर्भित करने के लिए 'थिरुनांगी' शब्द का उपयोग करें।

कोठी - कोठी एक विषम समूह है। 'कोठी' को जैविक पुरुषों के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो 'स्त्रीत्व' की अलग-अलग डिग्री दिखाते हैं - जो स्थितिजन्य हो सकता है। कोठियों में से कुछ उभयलिंगी व्यवहार करते हैं और किसी महिला से विवाह करते हैं। कोठियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति आम तौर पर निम्न होती है और कुछ लोग जीवनयापन के लिए यौन कार्य में संलग्न होते हैं।

हिजड़ा पहचान वाले कुछ लोग खुद को 'कोठियों' के रूप में भी पहचान सकते हैं। लेकिन सभी कोठी पहचान वाले लोग खुद को ट्रांसजेंडर या हिजड़ा नहीं मानते। जोगता/जोगप्पा: जोगता या जोगप्पा वे लोग होते हैं जो देवी रेणुखा देवी (येल्लम्मा) के प्रति समर्पित होते हैं और उनके सेवक के रूप में सेवा करते हैं, जिनके मंदिर महाराष्ट्र और कर्नाटक में मौजूद हैं। 'जोगता' उस देवी के पुरुष सेवक को संदर्भित करता है और 'जोगती' महिला सेवक को संदर्भित करता है (जिसे कभी-कभी 'देवदासी' भी कहा जाता है)।

कोई व्यक्ति ‘जोगता’ (या जोगती) बन सकता है यदि यह उसकी पारिवारिक परंपरा का हिस्सा है या यदि उसे कोई ‘गुरु’ (या ‘पुजारी’) मिल जाए जो उसे ‘चेला’ या ‘शिष्य’ के रूप में स्वीकार करता है। कभी-कभी, ‘जोगती हिजड़ा’ शब्द का इस्तेमाल उन पुरुष-से-महिला ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को दर्शाने के लिए किया जाता है जो देवी रेणुखा देवी के भक्त/सेवक हैं और जो हिजड़ा समुदायों में भी हैं। इस शब्द का इस्तेमाल उन्हें ‘जोगता’ से अलग करने के लिए किया जाता है जो विषम लैंगिक होते हैं और जो देवी की पूजा करते समय महिलाओं के कपड़े पहन सकते हैं या नहीं भी पहन सकते हैं। साथ ही, यह शब्द उन्हें ‘जोगती’ से

अलग करता है जो देवी को समर्पित जैविक महिलाएँ हैं। हालाँकि, 'जोगती हिजड़े' खुद को 'जोगती' (महिला सर्वनाम) या हिजड़ा और कभी-कभी 'जोगता' भी कह सकते हैं।

शिव-शक्तियाँ: शिव-शक्तियाँ ऐसे पुरुष माने जाते हैं जो देवी के वश में होते हैं या विशेष रूप से देवी के करीब होते हैं और जिनमें स्त्रीलिंग अभिव्यक्ति होती है। आमतौर पर, शिव-शक्तियों को वरिष्ठ गुरुओं द्वारा शिव-शक्ति समुदाय में शामिल किया जाता है, जो उन्हें उनके द्वारा पालन किए जाने वाले मानदंड, रीति-रिवाज और अनुष्ठान सिखाते हैं।

एक समारोह में, शिव-शक्तियों का विवाह एक तलवार से होता है जो पुरुष शक्ति या शिव (देवता) का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार शिव-शक्तियाँ तलवार की दुल्हन बन जाती हैं। कभी-कभी, शिव-शक्तियाँ क्रॉस-ड्रेस पहनती हैं और ऐसे सामान और आभूषण पहनती हैं जो आम तौर पर/सामाजिक रूप से महिलाओं के लिए होते हैं। इस समुदाय के अधिकांश लोग निम्न सामाजिक-आर्थिक स्थिति से ताल्लुक रखते हैं और ज्योतिषी, भविष्य वक्ता और आध्यात्मिक उपचारक के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं; कुछ लोग भिक्षा भी मांगते हैं।

तीसरे लिंग या ट्रांसजेंडर लोगों को सामाजिक बहिष्कार को छोड़कर स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, शिक्षा के क्षेत्र में कई तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यह सर्व विदित है कि हिजड़ों/ट्रांसजेंडरों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन सभी समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाना चाहिए।

यूएनडीपी द्वारा दिसंबर 2010 में किए गए विस्तृत शोध के आधार पर निम्नलिखित अनुशंसा की गई है:

1. एचआईवी की रोकथाम के लिए शोध करने, वित्तीय सहायता के लिए हिजड़ों/ट्रांसजेंडरों के लिए रणनीतिक स्थानों पर एचआईवी निगरानी केंद्र स्थापित करना और प्रभावी कार्यक्रमों को लागू करने के लिए सीबीओ की क्षमता का निर्माण करना।

2. जोखिमों के संरचनात्मक निर्धारकों को संबोधित करने और जोखिमों के प्रभाव को कम करने पर ध्यान केंद्रित करें, जैसे मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, नशीली दवाओं और शराब का दुरुपयोग, आदि।

3. स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित करें ताकि वे हिजड़ों/टीजी को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में सक्षम और संवेदनशील बनें।

4. सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी की अस्पष्ट कानूनी स्थिति को स्पष्ट करें और लिंग परिवर्तन प्रदान करें और मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करें।

5. कलंक और भेदभाव को कम करने या खत्म करने के लिए समाज के जमीनी स्तर पर जागरूकता फैलाना।

6 . जरूरतमंद हिजड़ों/टीजी के लिए सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए अधिक धन आवंटित करें।

7.. नीति निर्माण और कार्यक्रम विकास में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें।

भारतीय संविधान के तहत अधिकार और संरक्षण:- भारत का संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। यह भारत के सभी लोगों और नागरिकों के हितों की रक्षा कर रहा है। कुछ विशिष्ट प्रावधान हैं जिन्हें हम भारतीय संविधान से ले सकते हैं। ए. अनुच्छेद 14 और ट्रांसजेंडर:-

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाम अरुणाचल प्रदेश राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है:

“हम कानून के शासन द्वारा शासित देश हैं। हमारा संविधान प्रत्येक मनुष्य को कुछ अधिकार और नागरिकों को कुछ अन्य अधिकार प्रदान करता है। प्रत्येक व्यक्ति कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण का हकदार है।”

अनुच्छेद 14 में प्रावधान है कि राज्य भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। समानता में सभी अधिकारों और स्वतंत्रता का पूर्ण और समान आनंद शामिल है। समानता के अधिकार को संविधान की मूल विशेषता घोषित किया गया है और समानों को असमान या असमानों को समान मानना संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन होगा।

जैसा कि अनुच्छेद 14 सभी व्यक्तियों को समान सुरक्षा सुनिश्चित करता है, वैसे ही ट्रांसजेंडर को भी। यह अधिकार लिंग के आधार पर किसी को भी कानून के समान संरक्षण तक सीमित नहीं करता है। ट्रांसजेंडर या हिजड़े पुरुष या महिला की अभिव्यक्ति के अंतर्गत नहीं आते हैं, लेकिन 'व्यक्ति' शब्द एक व्यापक शब्द है। हिजड़े कानूनों के कानूनी संरक्षण के हकदार हैं और राज्य जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और समान सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। इसलिए, यौन अभिविन्यास या लिंग पहचान के आधार पर भेदभाव कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण को बाधित करता है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।

बी. अनुच्छेद 15 और 16 और ट्रांसजेंडर:- भारत के संविधान के भाग III के ये दो प्रावधान सार्वजनिक स्थानों तक समान पहुंच और रोजगार में समान अवसर सुनिश्चित करते हैं। अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के साथ, अन्य बातों के साथ-साथ, लिंग के आधार पर, (ए) दुकानों, सार्वजनिक रेस्तरां, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों तक पहुंच के संबंध में भेदभाव नहीं करेगा; या (ख) कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों का उपयोग, जो पूर्णतः या आंशिक रूप से राज्य निधि से बनाए गए हों या आम जनता के उपयोग के लिए समर्पित हों।

अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति या रोजगार से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसरों की समानता होगी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 (2) इस प्रकार है: "16(2)। कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर राज्य के अधीन किसी भी रोजगार या पद के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा।"

अनुच्छेद 16 न केवल सार्वजनिक रोजगार में लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, बल्कि राज्य पर यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य भी डालता है कि राज्य द्वारा रोजगार और नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाए। अनुच्छेद 15 और 16 के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति द्विआधारी लिंग में फिट नहीं होते हैं उन्हें अधिक सुरक्षा और देखभाल की आवश्यकता है। अनुच्छेद 15 और 16 में प्रयुक्त 'लिंग' शब्द केवल पुरुष या महिला के जैविक लिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जो स्वयं को न तो पुरुष मानते हैं और न ही महिला। राज्य ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) को सार्वजनिक सेवाओं में लाभ देने के लिए टीजी/हिजड़ों को वर्ग दिया है। राज्य द्वारा इस वर्ग को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में सशक्त बनाने के लिए कई सकारात्मक कदम उठाए गए हैं।

सी. अनुच्छेद 19(1)(ए) और ट्रांसजेंडर:- संविधान का अनुच्छेद 19(1) कुछ मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, जो राज्य की उन अधिकारों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति के अधीन है। अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकार किसी ऐसे व्यक्ति को उपलब्ध नहीं हैं जो भारत का नागरिक नहीं है। अनुच्छेद 19(1) उन महान बुनियादी अधिकारों की गारंटी देता है जिन्हें एक स्वतंत्र देश के नागरिक की स्थिति में निहित प्राकृतिक अधिकारों के रूप में मान्यता प्राप्त है और उनकी गारंटी है।

संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) में कहा गया है कि सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा, जिसमें किसी व्यक्ति का अपने स्वयं के पहचाने गए लिंग की अभिव्यक्ति का अधिकार भी शामिल है। स्वयं के पहचाने गए लिंग को पोशाक, शब्दों, क्रिया या व्यवहार या किसी अन्य रूप में व्यक्त किया जा सकता है।

संविधान के अनुच्छेद 19(2) में निहित प्रतिबंधों के अधीन किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत उपस्थिति या पोशाक की पसंद पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है।

डी. अनुच्छेद 21 और ट्रांसजेंडर:-

भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 इस प्रकार है:

21. जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण - किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा।"

अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों की बात करता है। जीवन का अधिकार बुनियादी मौलिक अधिकारों में से एक है और राज्य को भी उस अधिकार का उल्लंघन करने या उसे छीनने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 21 जीवन के उन सभी पहलुओं को शामिल करता है जो किसी व्यक्ति के जीवन को सार्थक बनाते हैं। किसी की लैंगिक पहचान की पहचान गरिमा के मौलिक अधिकार के केंद्र में है। जैसा कि पहले ही संकेत दिया जा चुका है, लिंग किसी व्यक्ति के अस्तित्व की भावना का मूल है और साथ ही किसी व्यक्ति की पहचान का अभिन्न अंग भी है। इसलिए लैंगिक पहचान की कानूनी मान्यता हमारे संविधान के तहत गारंटीकृत गरिमा और स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है।

अनुच्छेद 21 मानव जीवन की गरिमा, किसी की व्यक्तिगत स्वायत्तता, किसी की निजता के अधिकार आदि की रक्षा करता है। गरिमा के अधिकार को संविधान का एक अनिवार्य हिस्सा माना गया है।

जीवन का अधिकार और मनुष्य होने के नाते सभी व्यक्तियों को प्राप्त होता है। जैसा कि पहले ही संकेत दिया गया है, अनुच्छेद 21 किसी व्यक्ति की "व्यक्तिगत स्वायत्तता" की

सुरक्षा की गारंटी देता है। **अनुज गर्ग बनाम होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया** में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि व्यक्तिगत स्वायत्तता में दूसरों के हस्तक्षेप के अधीन न होने का नकारात्मक अधिकार और व्यक्तियों का अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने, खुद को व्यक्त करने और किन गतिविधियों में भाग लेना है, इसका चयन करने का सकारात्मक अधिकार दोनों शामिल हैं।

लिंग का आत्मनिर्णय व्यक्तिगत स्वायत्तता और आत्म-अभिव्यक्ति का एक अभिन्न अंग है और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दायरे में आता है। ई. राज्य की नीतियों के निर्देशक सिद्धांत:- अच्छे शासन के प्रतीक के रूप में "राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत" (भाग-IV) के रूप में राज्य। यह वह भाग है जो हमारे संविधान को एक आदर्श और उद्देश्य प्रदान करता है और कुछ सिद्धांतों को चित्रित करता है जो देश के शासन में मौलिक हैं।

डॉ. अंबेडकर ने इन निर्देशक सिद्धांतों के उद्देश्य को इस प्रकार समझाया था (संविधान सभा की बहस देखें): "निर्देशक सिद्धांत निर्देशों के उपकरणों की तरह हैं जो ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत गवर्नर-जनरल और उपनिवेशों के राज्यपालों और भारत के राज्यपालों को जारी किए गए थे।

जिसे "निर्देशक सिद्धांत" कहा जाता है वह निर्देशों के उपकरण का ही दूसरा नाम है। एकमात्र अंतर यह है कि वे विधायिका और कार्यपालिका को निर्देश हैं। जो कोई भी सत्ता पर कब्जा करता है, वह इसके साथ अपनी मर्जी से कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र नहीं होगा। इसके प्रयोग में उसे निर्देशों के इन उपकरणों का सम्मान करना होगा जिन्हें निर्देशक सिद्धांत कहा जाता है"।

एफ. ट्रांसजेंडर पर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय:- नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने सुनील बाबू पंत और अन्य में। बनाम नेपाल सरकार, ने ट्रांसजेंडरों के अधिकारों पर इस प्रकार बात की:- “संविधान के भाग II के अंतर्गत शामिल मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों को गारंटीकृत लागू करने योग्य मौलिक मानवाधिकार हैं।

इस कारण से, भाग III में निर्धारित मौलिक अधिकार तीसरे लिंग के लोगों को मानव के रूप में समान रूप से निहित अधिकार हैं। समलैंगिक और तीसरे लिंग के लोग भी अन्य पुरुषों और महिलाओं की तरह ही मनुष्य हैं, और वे इस देश के नागरिक भी हैं... इस प्रकार, ‘पुरुषों’ और ‘महिलाओं’ के अलावा अन्य लोगों, जिनमें ‘तीसरे लिंग’ के लोग भी शामिल हैं, के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। राज्य को पुरुषों और महिलाओं के अलावा तीसरे लिंग के लोगों सहित सभी प्राकृतिक व्यक्तियों के अस्तित्व को मान्यता देनी चाहिए। और यह

संविधान के भाग III द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों का आनंद लेने से तीसरे लिंग के लोगों को वंचित नहीं कर सकता है।" डॉ. मोहम्मद असलम खाकी और अन्य में पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। वी. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) रावलपिंडी एवं अन्य को किन्नरों के अधिकारों पर विचार करने का अवसर मिला और उन्होंने इस प्रकार निर्णय दिया:-

"यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि किन्नर अपने अधिकारों में इस देश के नागरिक हैं और इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान के संविधान, 1973 के अधीन, उनके अधिकार, जीवन और सम्मान के अधिकार सहित दायित्व समान रूप से संरक्षित हैं। इस प्रकार, किसी भी कारण से, उनके विरुद्ध कोई भेदभाव संभव नहीं है, जहाँ तक उनके अधिकारों और दायित्वों का संबंध है। संघीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर सरकारी अधिकारी उन्हें जीवन और संपत्ति की सुरक्षा प्रदान करने और उनकी गरिमा को सुरक्षित रखने के लिए बाध्य हैं, जैसा कि अन्य नागरिकों के मामले में किया जाता है।"

निष्कर्ष:-

ट्रांसजेंडर या हिजड़े समाज का अभिन्न अंग हैं। भारत के संविधान ने विभिन्न स्तरों पर इस वर्ग को समाज का अंग माना है। नाज फाउंडेशन बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ तथा नवतेज सिंह जौहर एवं अन्य बनाम भारत संघ के निर्णय ने भारतीय समाज में LGBTQ समुदाय की स्थिति निर्धारित की है। भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को अपराध मुक्त कर दिया गया है। उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि अनुच्छेद 14, 15, 16, 19 और 21 हिजड़ों/ट्रांसजेंडरों को इसके दायरे से बाहर नहीं रखते हैं तथा इस समुदाय को क:ई चरणों में उचित स्थान और प्रतिनिधित्व मिला है। यह पर्याप्त नहीं है तथा अभी और भी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है।

संदर्भ

1. अस्तित्व का अधिकार: उन्नीसवीं सदी के भारत में हिजड़े और राज्य लॉरेंस डब्ल्यू. प्रेस्टन आधुनिक एशियाई

अध्ययन, खंड 21, संख्या 2 (1987), पृ. 371-387

2. अनुज गर्ग बनाम होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (2008) 3 एससीसी 1 (पैराग्राफ 34-35)

3. डॉ. मोहम्मद असलम खाकी और अन्य बनाम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) रावलपिंडी और अन्य।

(संविधान याचिका संख्या 43/2009) 22 मार्च, 2011 को तय हुई।

4. भारत में हिजड़े/ट्रांसजेंडर महिलाएं: एचआईवी, मानवाधिकार और सामाजिक बहिष्कार, भारत पर यूएनडीपी रिपोर्ट

मुद्दा: दिसंबर, 2010

5. भारतीय दंड संहिता, 1860

6. कैथरीन एम. फ्रेंक, लिंग भेदभाव कानून की केंद्रीय गलती: लिंग से लिंग का पृथक्करण

, 144 यू.पीए.रेव.1,3 (1995)

7. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाम अरुणाचल प्रदेश राज्य एआईआर 1996 एससी 1234

8. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ। [(2014) 5 एससीसी 438]

9. नवतेज सिंह जौहर एवं अन्य बनाम भारत संघ थ्रू। सचिव विधि एवं न्याय मंत्रालय, डब्ल्यू.पी. (सीआरएल.) संख्या 76

2016

10. नाज फाउंडेशन बनाम नई दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार एवं अन्य, डब्ल्यूपी (सी) संख्या 7455/2001

11. न तो पुरुष और न ही महिला हिजड़ा ऑफ इंडिया, सेरेना नंदा, वड्सवर्थ पब्लिशिंग कंपनी, दूसरा संस्करण

12. भारत का संविधान, 1950

13. जनजातीय अपराधीकरण अधिनियम

14. यूएनडीपी इंडिया रिपोर्ट (दिसंबर, 2010)

15. यूनिलबाबू पंत एवं अन्य बनाम नेपाल सरकार (रिट याचिका संख्या 917 ऑफ 2007, 21 दिसंबर, 2007 को निर्णयित)

16. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी-भारत)

17. वर्ष 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (यूडीएचआर)

18. जागरण संवाददाता 16 अप्रैल 2014

19. राज एक्सप्रेस ,समाचार पत्र, इंदौर, 30 अगस्त 2024, पृष्ठ संख्या 8